

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, संवाई माधोपुर

अपील संख्या - 24/24

GCMS NO 2024/74

1. मुरारी पुत्र तबलू
2. बाबूलाल
3. कमलेश
4. मु०दीपू पिसरान कन्नू समस्त जातियान कोली निवासीयान महूडब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
5. अलीशेर पुत्र अल्लार खां
6. अमरदीन पुत्र सम्पत
7. बबलू पुत्र दीना
8. बाबू पुत्र सम्पत
9. रहीम पुत्र सम्पत
10. शहीद पुत्र दीना
11. सत्तार पुत्र दीना
12. सीराज पुत्र दीना समस्त जातियान तेली निवासीयान महूडब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम



1. महेंद्र कुमार
2. सुरेन्द्र कुमार पिसरान लक्ष्मीनारायण
3. प्राची पत्नि सुरेन्द्र कुमार
4. राधा पत्नि महेंद्र कुमार
5. बलदेव पुत्र जगराम सोनी जातियान सुनार निवासीयान महूडब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. देवेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह सोलंकी जाति जाट निवासी महूडब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेसपो०

(अपील विरुद्ध निर्णय मु०नं० 72/22 दिनांक 6.12.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला० श्री पी०एल०गोयल

अभिभाषक रेसपो० श्री ईश्वर सोनी

दिनांक 25.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 6.12.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पेश की है ।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
संवाई माधोपुर

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा 5 ता 12 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि ख0न0 810 ग्राम महुइब्राहिमपुर से प्रार्थीगण के खेतों को आने जाने का एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ता आम के दक्षिण में अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख0न0 789,790,846,877 के दक्षिण एवं पूर्व दिशा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात ख0न0 879,878,852,861 स्थित ग्राम महु इब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन स्थित है। प्रार्थीगण की आराजीयात को कृषि साधन व मवेशियों को लाने व ले जाने बाबत एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेतों की डोल पर होकर विगत सैकड़ों साल से मौजूद रहा है। अप्रार्थीगण के खेत ख0न0 889,890,846,877 की डोल से गुजरने वाला रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतों के साथ साथ अन्य खातेदारान के खेतों को भी उपलब्ध एक मात्र रास्ता है। उक्त समस्त खातेदारान अपनी अपनी सहमति से एक दुसरे की खातेदारी के खेतों की डोल में डके सहारे सहारे होकर उपलब्ध रास्ते में होकर आते जाते हैं। वही क्रम आज भी बदस्तूर है। जिसका खातेदारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। खसरा न0 790 आम रास्ते के सहारे स्थित होने के कारण अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी का बेजा लाभ उठाकर प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने पर आमादा है। जिसमें खेत ख0न0 846, 877 के खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का सहयोग करते हैं। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतों में होकर हालांकि चालू है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के आवागमन में मवेशियों के आवागमन एवं कृषि साधनों के आवागमन में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा न0 890 की पूर्वी डोल पर होकर जा रहे रास्ते को कटीले तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से पुछा तो उनके द्वारा कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी में दर्ज है इसलिए इस रास्ते को हमने बंद कर दिया है। अब इस रास्ते से प्रार्थीगण को नहीं निकलने देंगे। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमियों को काशत की सहूलियत बाबत अप्रार्थीगण की खातेदारी में से 20 फीट चौड़ा रास्ता सम्पूर्ण लम्बाई में ख0न0 810 रास्ते से लेकर ख0न0 852 की उत्तरी डोल तक नियमानुसार दिलाया जावे जिसकी ऐवज में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण खातेदारान को भूमि का मूल्य अदा करने को तैयार है। अतः खसरा न0 810 से लेकर ख0न0 790,789 की पूर्वी डोल पर होकर 846 में होते हुए ख0न0 879,878 की पश्चिमी डोल पर होकर ख0न0 877 व 876 की मध्य डोल पर होकर ख0न0 861 तक प्रार्थीगण को 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमियों को काशत करने हेतु दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की तरमीम रेवेन्यू शीट में दर्ज कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा 5 ता 12 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।



अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की अपील पर सुनी गई।

  
 अधिनस्थ न्यायालय  
 जयपुर

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह कही नहीं बताया कि आवेदकगण को अपनी भूमि ख0न0 852,861,878,879 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में होकर अन्य कहीं किसी जगह होकर रास्ता रहा हो तथा उक्त स्थिति के संबंध में अप्रार्थीगण ने भी अपने जबाब में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है जबकि मुताबिक कानून उक्त प्रावधान के अनुसार कृषि जोतो के लिए काश्तकार को अपनी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने बाबत उक्त प्रावधान बनाया गया है, ऐसी स्थिति में जब आवेदकगण/अपीलांटस को अपनी भूमि में कृषि जोतो हेतु आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है और वह अप्रार्थीगण/रेस्पो0 की भूमि में होकर बुजुर्गान बजमाने आवागमन कर अपनी भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त स्थिति के मुताबिक कानून अप्रार्थीगण की भूमि में होकर अपीलांटस रास्ता प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर आदेश खिलाफ कानून पारित किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता दिये जाने पर कई खातेदारों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रेस्पो0 ने यह कही नहीं बताया कि उनकी भूमि में होकर रास्ता देने पर उन्हें क्या और किस प्रकार की असुविधा होगी, जबकि उक्त भूमि में होकर रास्ता देने पर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 उनकी भूमि की सरकारी रेट से तीन गुनी राशि प्राप्त करने और उक्त रास्ता प्रार्थीगण/अपीलांट का निजी रास्ता ना होकर सभी खातेदारों के उपयोग हेतु रिकार्ड में सरकारी रास्ता का काम किया जाता, ऐसी स्थिति में रेस्पो0 के उक्त रास्ता दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति को इग्नोर कर खिलाफ कानून आदेश पारित किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उक्त खसरा नम्बरो पर कोई रास्ता मौजूद नहीं होना कहा है, इसके साथ उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलांटस को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो, ऐसा कोई भी अंकन तहसीलदार की रिपोर्ट में नहीं है। इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत रेवई व सरपंच ग्राम पंचायत मौसला व सरपंच ग्राम पंचायत महूडब्राहिमपुर के द्वारा भी इस संबंध में अपने लेटरहेड पर यह स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि में होकर ही लोग आते जाते हैं तथा इस संबंध में मौके के फोटोग्रॉफ जिनमें उक्त भूमि में आवागमन से मौके पर रास्ते के अलामात मौजूद है तथा अपीलांट को अपनी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, मगर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ने बसाज न्यायालय ने आवश्यकता से अधिक महत्व देकर प्रार्थीगण/अपीलांटस की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य को इग्नोर कर सरसरी तौर पर उक्त आदेश विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.9.23 को वकील प्रार्थीगण की ओर से मौके की जाँच हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके जबाब हेतु दिनांक 9.10.23 व 26.10.23 नियत की गई तथा दिनांक 28.11.23 को दिनांक 26.9.23 में पेश प्रार्थना पत्र का जबाब अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में पेश करना और उसे रिकार्ड पर लेना आदेशिका में अंकित किया गया तथा प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त होना भी आदेशिका में अंकित कर दिनांक 26.9.23 को प्रार्थीगण द्वारा इस हेतु पेश प्रार्थना

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

पत्र को खारिज कर दिया, जबकि पूर्व में तहसीलदार की मौके की जाँच रिपोर्ट किस आदेश से या किस प्रार्थना पत्र पर मंगाई गई, यह सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में वर्णित आदेशिकाओं में कही भी अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार की उक्त मौका रिपोर्ट किस आदेश के माध्यम से पत्रावली में संलग्न की गई है, ऐसा कोई भी आदेश सम्पूर्ण पत्रावली में नहीं है, इससे स्पष्ट है कि उक्त समस्त कार्यवाही बिना प्रार्थीगण को इस संबंध में सुनवाई का अवसर दिये बसाज अप्रार्थीगण की गई, जो कि न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। और इसी कारण तहसीलदार हिण्डौन द्वारा मौके के अनुसार रिपोर्ट नहीं देकर अप्रार्थीगण से साज कर गलत मौका रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिलकुल गलत आदेश पारित किया गया, इसलिए प्रकरण को उक्त आधार पर रिमाण्ड फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। रेस्पोंड अधिवक्ता के द्वारा अपील को डिले से पेश किये जाने हेतु आधार लिया है और यह तर्क दिया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 24.1.24 को हो गई तो उनके द्वारा अपील दायर करने की मियाद दिनांक 6.2.24 तक अपील क्यों नहीं पेश की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है जबकि इस संबंध में अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त दिनांक को आदेश की नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह मशविरा लेने में दिनांक 6.2.24 तक की समयावधि निकल गई तत्पश्चात् ही अपीलांटस दिनांक 24.1.24 को इल्म की तिथि से अन्दर दो माह अपील किया है इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षकारों के अधिकारों का मैरिट पर निस्तारण होना हो, वहाँ मियाद के बिन्दु को टेक्नीकल रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूप अपीलांटस को उसे कन्डोन किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना कानूनन आवश्यक है, इसलिए रेस्पोंड का मियाद के बिन्दु का तर्क भी आधारहीन है। रेस्पोंड अधिवक्ता का तर्क था कि अपीलांट न० 3 व 4 मूल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं थे क्योंकि मूल प्रार्थना पत्र के टाइटल में प्रार्थी क्रमांक 3 व 4 का कॉलम खाली है जबकि अपील में कमलेश व दीपू को प्रार्थी संख्या 3 व 4 गलत रूप से पक्षकार बनाया है, इस संबंध में मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी संख्या 3 व 4 का अंकन होने से रह गया जबकि मूल प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण में अपीलांट संख्या 3 व 4 दर्ज है और उनके उस निशानी हो रही है अर्थात् कमलेश व दीपू पिसरान कन्डोन की प्रार्थीगण में अंकित नामों के साथ निशानी है इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों पक्षकार प्रकरण में प्रार्थी रहे हैं इसलिए अपील में उन्हें पक्षकार न० 3 व 4 बनाया गया है इसलिए रेस्पोंड का उक्त तर्क भी आधारहीन व निरर्थक है। और अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। इसी प्रकार रेस्पोंड का तर्क था कि प्रार्थीगण का खेतों को आने जाने का रास्ता ख०न० 810 में है इसलिए अपीलांटस को प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है और प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के तहत पोषनीय नहीं है। यकां तर्क बिलकुल गलत है क्योंकि प्रार्थीगण ख०न० 810 जो कि गैर मुमकिन रास्ता प्रार्थीगण के खेतों के उत्तर की ओर रहा है उसमें से होकर प्रार्थीगण दक्षिण में स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी खेत ख०न० 789,790,846,877 के दक्षिण एवं पूर्व दिशा में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख०न० 879,878,852,861 ग्राम महूडब्राहिमपुर में आते जाते हैं इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में उत्तर की ओर स्थित ख०न० 810 गैर मुमकिन रास्ते में होकर दक्षिण में स्थित अपनी भूमि में अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर आवागमन करते हैं इसलिए भी रेस्पोंड का उक्त तर्क निरर्थक व आधारहीन है। इसी प्रकार रेस्पोंड अधिवक्ता

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

का तर्क रहा कि अपीलान्टस ने विवादित आराजीयात के सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है बिलकुल गलत रहा है। जबकि अपीलान्टस के द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा ही परेशान कर रास्ता नहीं दिया जा रहा था जबकि शेष व्यक्तियों अर्थात् अन्य खातेदारान द्वारा रास्ता दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण हाजा में संबंधित ख0न0 के खातेदारान को प्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है जो अपीलान्टस व रेस्प0 के रूप में प्रकरण में समाहित है। इसलिए रेस्प0 का उक्त तर्क भी आधारहीन है अगर ऐसा वास्तव में होता तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उक्त तर्क को आवश्यक रूप से डिस्कस किया जाता तथा उक्त तर्क के संबंध में रेस्प0 ने जबाब प्रार्थना पत्र में कही कोई उज्र नहीं लिया है और ना ही ऐसी स्थिति में ऐसी किसी तर्क को अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में डिस्कस किया है इसलिए अपील की स्टेज पर उक्त तर्क को रेस्प0 लेने के मुताबिक साक्ष्य अधिनियम विबंधित/स्टोपड है, इसलिए रेस्प0 का उक्त तर्क भी आधारहीन है। रेस्प0 के अधिवक्ता का तर्क रहा कि अपीलान्टस/प्रार्थीगण द्वारा जिन नक्शा नम्बरो में से रास्ता चाहा है उनकी नक्शा ट्रेस की प्रति अपूर्ण पेश की है जिसमें ख0न0 810 को अपूर्ण दिखाया गया है जबकि जबाब अप्रार्थीगण के साथ पेश नक्शा ट्रेस का प्रार्थीगण द्वारा पेश नक्शा ट्रेस से मिलान करने पर प्रार्थीगण का नक्शा ट्रेस अपूर्ण पेश किया है इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बिलकुल सही खारिज किया है। रेस्प0 का उक्त तर्क भी गलत माने जाने योग्य नहीं है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने यह कही नहीं बताया कि ख0न0 810 जो कि गैर मुमकिन रास्ता रहा है, उक्त रास्ता प्रार्थीगण/अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि तक जाता हो यह कही भी रेस्प0 ने नहीं बताया और अपीलान्टस की भूमि तक उक्त रास्ता जाता हो, ऐसा नक्शा ट्रेस में कोई अंकन नहीं है। बल्कि नक्शा ट्रेस के मुताबिक ख0न0 810 गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 786 की पूर्वी डोल से लगवा ख0न0 785 के मुहाने तक जो कि ख0न0 786 की पूर्वी डोल के आधे भाग पर ही रह जाता है तक है, न कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतों तक। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने यह कही भी स्पष्ट नहीं किया कि जो नक्शा ट्रेस पेश किया है जो प्रार्थीगण के रास्ते के क्लेम को समाप्त करता हो, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का रेस्प0 का उक्त तर्क भी रिकार्ड के विपरीत होने से महत्वहीन व आधारहीन है। तथा प्रकरण प्रार्थीगण के खेतों के आवागमन में व फसल के बुवाई, सिंचाई व उसके कटाई आदि को ले जाने व लाने के साधनों के उपयोग के संबंध में जो कि प्रार्थीगण के खेतों तक पहुँच सके और प्रार्थीगण खेतों का सुचारु उपयोग कर सके के बाबत पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में होकर प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को पूर्णरूपेण विधिक रूप से साबित किया है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण स्थिति को ओवरलुक करते हुए उक्त आदेश विधि विरुद्ध पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता प्रदान किया जाकर रास्ते का अमल राजस्व रिकार्ड में किया जावे, बसूरत दीगर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिकाओं के विपरीत प्रकरण में कार्यवाही करने व बिना आदेश के प्रकरण में तहसीलदार



राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

हिण्डौन से मौका रिपोर्ट मंगाने के आधार पर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने हेतु और नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता का दौरान बहस कथन रहा कि प्रार्थीगण/अपीलांटस की किसी भी आराजीयात को कृषि साधन लाने व ले जाने के बाबत कोई एक मात्र रास्ता रेस्पोंडेंट के खेतों की डोल पर होकर विगत वर्षों से या कभी भी मौजूद नहीं रहा है ना ही वर्तमान में है। इस प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नक्शा में लाल रंग की डोटेड लाईन से रास्ता गलत दर्शित किया है एवं नक्शा भी अपूर्ण पेश किया है। जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में डिसकस किया है एवं नक्शे का अपूर्ण माना है। बल्कि ख०न० 810 गैर मुमकिन रास्ता, ख०न० 786 व 785 के मध्य होकर उक्त दोनों खसरा नम्बरान की दक्षिणी डोल तक ख०न० 783 के लिए जाता है। खसरा न० 846 एवं 877 की डोल पर होकर कोई रास्ता ख०न० 810 तक नहीं जाता है। जिसे तहसीलदार द्वारा अपने मौका रिपोर्ट में माना है। प्रार्थीगण जबरन कानून का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोंडेंट की आराजीयात में से रास्ता चाहते हैं। अपीलांट द्वारा अपील में अपीलांट संख्या 3 व 4 को अलग से पक्षकार बनाया गया है जबकि अपीलांट संख्या 3 व 4 अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं थे। इस प्रकार अपीलांट के कुसयोजन से भी अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। इसी प्रकार प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा ख०न० 846 में से भी रास्ते की मांग की गई है जबकि उनको पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। उक्त ख०न० 846 जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जगन्नाथ को ही बनाया है उनके जायज वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार ख०न० 879 में से भी रास्ते की मांग अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा की गई थी परन्तु ख०न० 879 के खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अपील पेश करने में हुई देरी का कारण नकल प्राप्त करना एवं कानूनी सलाह लेने के कारण अपील पेश करने में बिलम्ब हुआ है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा ही पेश किया था जिसके निर्णय की जानकारी अपीलांटस/प्रार्थीगण को शुरू से ही थी। इस कारण अपीलांट का यह कथन मिथ्या है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील 57 दिवस डिले से पेश की गई है। जिसके डिले का कोई विधिक कारण का उल्लेख भी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में नहीं किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार हिण्डौन से मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रार्थीगण/अपीलांटस व अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधिवत विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 251 ए प्रस्तुत कर ग्राम महुडब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली के खसरा न० 810 से लेकर ख०न० 790,789

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

की पूर्वी डोल पर होकर 846 मे होते हुए ख0न0 879,878 की पश्चिमी डोल पर होकर ख0न0 877 व 876 की मध्य डोल पर होकर ख0न0 861 तक प्रार्थीगण को 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमियो को काशत करने हेतु रास्ता चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ते के संबंध मे तहसीलदार हिण्डौन सिटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार हिण्डौन महुवा रोड से लिंक गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 810 ग्राम महूइब्राहिमपुर मौके पर चालू बताया गया है। उक्त रास्ते के दक्षिणी तरफ की भूमि की खातेदारी ख0न0 790, 789 रेस्प0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमे से होकर सैकडो वर्षो से अपीलांटगण/प्रार्थीगण अपने खेतो पर आवागमन होना बतात है परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त ख0न0 से कभी भी आवागमन नही रहा है। ना ही वर्तमान मे है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मिथ्या साबित है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्प0 द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अवलोकन से जाहिर है कि ख0न0 810 गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 786 व 785 के मध्य होकर गुजरता है। जो अपीलांटगण/प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर पहुँचता है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण/प्रार्थीगण की भूमियो पर पहुँच का रास्ता पूर्व से मौके पर मौजूद है। पूर्व से मौजूद रास्ते के अलावा अन्य रास्ते की मांग किया जाना राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 क के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार हिण्डौन सिटी की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्पूर्ण विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 72/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 6.12.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.8.2025को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(लक्ष्मी कान्त बालोत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील प्राधिकारी